eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

इक्कीसवीं सदी के भारत के पड़ोसी देशों से संबंध – अर्थनीति के विशेष संदर्भ में

डॉ0 अमित जायसवाल[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिन्दकी, फतेहपुर उ0प्र0

Received: 15 March 2025 Accepted & Reviewed: 25 March 2025, Published: 28 March 2025

Abstract

इक्कीसवी सदी में वैश्वीकरण, क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों ने भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया है। भारत की ”नेबरहुड फर्स्ट नीति“ के अंतर्गत व्यापार, ऊर्जा सहयोग, अवसंरचना विकास और मानवीय सहायता पर विशेष बल दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित आर्थिक दृष्टिकोण ने इस नीति की नींव रखी, जिसने विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रखकर समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का साधन माना। इस शोध–पत्र में भारत और उसके प्रमुख पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किन देशों के साथ सहयोग गहराया है और किन देशों के साथ राजनीतिक, सुरक्षा अथवा रणनीतिक चुनौतियाँ संबंधों को सीमित करती हैं। साथ ही, भारत की बहुपक्षीय मंचों (SAARC, BIMSTEC, BBIN, SCO) में भूमिका का आकलन भी किया गया है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारत की पड़ोसी नीति अवसर और चुनौतियों का सम्मिश्रण है, और इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या यह दक्षिण एशिया में स्थिरता, सहयोग और समृद्धि स्थापित कर सकती है।

बीज शब्द– भारत, पड़ोसी देश, आर्थिक संबंध, दक्षिण एशिया, नेबरहुड फर्स्ट, क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, बहुपक्षीय मंच, वैश्वीकरण।

Introduction

इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण, क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। विशेष रूप से पिछले एक दशक में, भारत की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक कूटनीतिक स्थिति में सुधार ने इसकी पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहभागिता को गहराया है। **नेबरहुड फर्स्ट नीति** के अंतर्गत क्षेत्रीय अवसंरचना, व्यापार विस्तार, ऊर्जा सहयोग और मानवीय सहायता को प्रमुखता दी गई है। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक दृष्टि ने इस नीति की वैचारिक नींव रखी। 1990 के दशक में जब भारत राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं से जूझ रहा था, तब अटल जी ने आर्थिक सुधारों को गति दी और उन मूल्यों को आगे बढ़ाया जिनमें विकास का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना था। उनकी दूरदर्शी सोच ने भारत को 21वीं सदी में वैश्विक नेतृत्व हेतु तैयार किया। आज की भारत की अर्थनीति उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है – संपर्क, समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता। यह शोध–पत्र भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, अवसंरचना परियोजनाएं, रणनीतिक सहयोग और बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता को सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना।

2. द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, अवसंरचना परियोजनाएं, रणनीतिक सहयोग और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की सहभागिता का अध्ययन करना।

3. नीति–निर्माताओं को व्यवहारिक सुझाव प्रदान करना।

अध्ययन की सीमा – यह अध्ययन भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर केंद्रित है। अध्ययन में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, अवसंरचना परियोजनाएं, रणनीतिक सहयोग और बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता को सम्मिलित किया गया है।

अनुसंधान पद्धति–

- प्रकार– वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन
- स्रोत– द्वितीयक स्रोत (सरकारी रिपोर्टें, नीति दस्तावेज)

पड़ोसियों के साथ आर्थिक संबंधों की अनिवार्यता– क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए आर्थिक सहभागिता आवश्यक भारत एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष और सीमा विवाद समय–समय पर उभरते रहते हैं। यदि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहभागिता को सुदृढ़ करता है, तो इससे न केवल व्यापार बढ़ता है, बल्कि आपसी निर्भरता शांति और सुरक्षा को भी मजबूती देती है। भारत की विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट केवल एक राजनीतिक घोषणापत्र नहीं बल्कि व्यवहारिक रणनीति है। भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाएँ, ऊर्जा व्यापार, और मानव संसाधन विकास पहल इस नीति को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया हैं। इसके अतिरिक्त भारत भारत क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना चाहता है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों से प्राथमिक सामग्री, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग और श्रमिक सहभागिता भारत को कम लागत और लोचशीलता की दृष्टि से लाभ देती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध हैं। इन संबंधों का लाभ उठाकर people to people contact को आर्थिक गतिविधियों में बदला जा सकता है। चीन ने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के माध्यम से दक्षिण एशिया में भारी निवेश किया है। यदि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत आर्थिक बंधन नहीं बनाएगा, तो यह रणनीतिक रूप से चीन के लिए एक खुला मैदान बन जाएगा। भारत के सीमावर्ती राज्यों की प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी सीमा पार व्यापार और अवसंरचना कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है।

भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध – द्विपक्षीय विश्लेषण– भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध उसके क्षेत्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण की रीढ़ हैं। इनमें सबसे सफल उदाहरण भारत–बांग्लादेश संबंध का है, जिसने पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2022–23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.2 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो इस क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

का सूचक है। व्यापार के अलावा ऊर्जा सहयोग इस संबंध का प्रमुख आधार बना है, जिसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश को 1160 मेगावाट से अधिक बिजली निर्यात कर रहा है। मैत्री पाइपलाइन, रेल संपर्क और डिजिटल भुगतान प्रणाली के साझा प्रयोग ने न केवल परस्पर निर्भरता को सुदृढ़ किया है, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और स्थिरता को भी गहरा किया है। नेपाल के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। खुले बॉर्डर और सांस्कृतिक निकटता के कारण यह संबंध अद्वितीय है, किंतु हाल के वर्षों में इसका आधार आधुनिक अवसंरचना और ऊर्जा सहयोग पर भी मजबूती से टिक गया है। जयनगर–बिजलपुरा रेल संपर्क, वीरगंज में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) और अमलेखगंज–पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसी परियोजनाएँ नेपाल की भारत पर आवश्यक आपूर्ति के लिए निर्भरता को और संगठित बनाती हैं। ये प्रयास यह दर्शाते हैं कि भारत न केवल पड़ोसी देश के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है बल्कि उसकी आर्थिक स्थिरता का भी आधार है। भूटान के साथ भारत का आर्थिक संबंध अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलविद्युत सहयोग इस साझेदारी की धुरी है। टाला और पुनत्सांगचू जैसी परियोजनाएँ भूटान को आय का बड़ा स्रोत प्रदान करती हैं और भारत को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराती हैं। यही नहीं, डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे रूपे के प्रयोग और पर्यावरणीय स्थिरता पर साझा प्रतिबद्धता ने इस संबंध को पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ाकर सतत विकास की दिशा में भी विस्तारित किया है। म्यांमार के साथ भारत का संबंध एक अलग प्रकार की चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर भारत को ASEAN से जोड़ने का प्रवेशद्वार होने के कारण म्यांमार भारत की Act East Policy का केंद्रीय तत्व है। भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट जैसी परियोजनाएँ भारत की क्षेत्रीय संपर्क रणनीति को दर्शाती हैं। हालांकि, म्यांमार की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता ने इन परियोजनाओं की गति को बाधित किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि पड़ोसी देशों की आंतरिक स्थिति भारत की आर्थिक कूटनीति को किस हद तक प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत, पाकिस्तान के साथ भारत का आर्थिक संबंध लगभग ठप है। राजनीतिक और सुरक्षा तनावों ने व्यापार को सीमित कर दिया है। वर्ष 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान का MFN दर्जा समाप्त कर देना इस अवरोध की औपचारिक पुष्टि थी। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार नगण्य है और संभावनाएँ राजनीतिक अविश्वास के कारण ठहर सी गई हैं।

चीन के साथ भारत का संबंध एक विरोधाभासी परिदृश्य प्रस्तुत करता है। वर्ष 2022–23 में दोनों देशों का व्यापार 115 अरब डॉलर तक पहुँच गया, किंतु इसका संतुलन चीन के पक्ष में अत्यधिक झुका हुआ है। भारत का निर्यात केवल 20 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि आयात 95 अरब डॉलर से अधिक। इस असंतुलन को कम करने के लिए भारत ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में बदलाव और PLI स्कीम जैसे उपाय अपनाए हैं। इस प्रकार भारत–चीन आर्थिक संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा, दोनों का मिश्रण है। अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत ने अपनी उपस्थिति को मानवीय और विकासात्मक सहायता पर आधारित रखा है। सलमा डैम और अफगान संसद भवन जैसी परियोजनाएँ भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने खाद्यान्न, दवाइयाँ और टीके भेजकर मानवीय सहयोग जारी रखा है। चाबहार पोर्ट और INSTC के माध्यम से भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अफगानिस्तान को क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध समान प्रकार के नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों और साझेदारी की प्रकृति के अनुसार भिन्न–भिन्न हैं। जहाँ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ परस्पर सहयोग और विकास आधारित संबंध स्थापित हुए हैं, वहीं पाकिस्तान और चीन के साथ यह संबंध राजनीतिक व रणनीतिक चुनौतियों से घिरे हुए हैं। म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ आंतरिक अस्थिरता भारत की पहल को सीमित करती है, लेकिन भारत की दीर्घकालिक दृष्टि यह है कि क्षेत्रीय संपर्क और साझेदारी को बनाए रखा जाए। अंततः भारत की पड़ोसी अर्थनीति अवसर और चुनौती दोनों का सम्मिश्रण है, जो उसकी 21वीं सदी की विदेश नीति का सबसे गतिशील और संवेदनशील पहलू है।

बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका– बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका उसके क्षेत्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) का भारत संस्थापक सदस्य रहा है, किंतु पाकिस्तान के कारण बार–बार उत्पन्न गतिरोध और आंतरिक असहमति ने इसे लगभग निष्क्रिय बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारत ने क्षेत्रीय सहयोग के वैकल्पिक मंचों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi&Sectoral Technical and Economic Cooperation) में भारत सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। यह मंच न केवल समुद्री सहयोग और ऊर्जा संपर्क को प्रोत्साहित करता है, बल्कि दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। इसी तरह, BBIN (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal) पहल भारत की प्रगतिशील और व्यावहारिक साझेदारी का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत सड़क परिवहन, ट्रांजिट और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सीधे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भारत की सदस्यता अपेक्षाकृत नई है, किंतु इसकी भूमिका रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। SCO के माध्यम से भारत आतंकवाद–निरोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय संवाद को आगे बढ़ाता है। इन सभी मंचों में भारत की भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी की ओर भी बढ़ रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बहुपक्षीय संदर्भ में भी जोड़कर देखता है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापारिक अवसर और सामरिक संतुलन तीनों सुनिश्चित किए जा सकें।

भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण– भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रत्येक देश के साथ सहयोग की प्रकृति, गहराई और रणनीतिक महत्त्व अलग–अलग है। बांग्लादेश के साथ 18.2 अरब डॉलर का व्यापार, ऊर्जा निर्यात, डिजिटल संपर्क और कपड़ा उद्योग में सहयोग ने इसे भारत के लिए पूर्वी संपर्क का सबसे मजबूत आधार बनाया है। नेपाल के साथ लगभग 9.3 अरब डॉलर का व्यापारिक संबंध खुले बॉर्डर, ईंधन पाइपलाइन, रेल संपर्क और एकीकृत चेक पोस्ट जैसी परियोजनाओं पर आधारित है, जो न केवल सांस्कृतिक निकटता को बल्कि भौगोलिक अनिवार्यता को भी दर्शाता है। भूटान के साथ व्यापारिक संबंध तुलनात्मक रूप से छोटे, लगभग 1.2 अरब डॉलर के हैं, किंतु जलविद्युत और पर्यावरणीय सहयोग के कारण यह साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। म्यांमार के साथ लगभग 3.4 अरब डॉलर के व्यापार का आधार

क्षेत्रीय संपर्क और ट्रांजिट परियोजनाएँ हैं, जिनसे भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को ASEAN बाजारों से जोड़ना चाहता है।

सारणी (Table-1) **तुलनात्मक तालिकारू भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग**

(कोष्ठक में आंकड़ों के स्त्रोत लिखे हैं)

देश	**व्यापार ($Billion)**	**सहयोग क्षेत्र**	**रणनीतिक महत्व**
बांग्लादेश	18.2 (WITS/World Bank, 2022)	ऊर्जा, डिजिटल, कपड़ा	पूर्वी संपक
नेपाल	8.68 (TrendEconomy, 2022)	ईंधन, रेल, बॉर्डर ICP	सांस्कृतिक–भौगोलिक सहयोग
भूटान	~1.2 (Govt. of Bhutan, 2022)	जलविद्युत, पर्यावरण	ऊर्जा साझेदारी
म्यांमार	3.4 (DGFT, 2022)	संपर्क, व्यापार	पूर्वोत्तर से ASEAN संपर्क
चीन	115 (DGFT, 2022–23)	हार्डवेयर, आयात–निर्यात	प्रतिस्पर्धी पड़ोसी
पाकिस्तान	<0.2 (DGFT, 2022)	सीमित व्यापार	रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी
अफगानिस्तान	मानवतावादी	दान, निर्माण	मध्य एशिया संपर्क

चीन के साथ संबंध सबसे बड़े पैमाने पर हैं, जहाँ व्यापार 115 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, किंतु यह भारत के लिए भारी व्यापार घाटे का कारण भी है। चीन के साथ संबंध प्रतिस्पर्धा और सहयोग का मिश्रण हैं, और भारत की रणनीति यहाँ आत्मनिर्भरता और संतुलन पर आधारित है। पाकिस्तान के साथ व्यापार नगण्य है, 0.2 अरब डॉलर से भी कम, और यह लगभग पूरी तरह से राजनीतिक तनावों का शिकार हो चुका है, जिससे यह संबंध अधिकतर रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक बनकर रह गया है। अफगानिस्तान की स्थिति अलग है, जहाँ भारत का सहयोग मुख्यतः मानवीय सहायता, निर्माण परियोजनाओं और क्षेत्रीय संपर्क (विशेषकर चाबहार पोर्ट के माध्यम से) पर केंद्रित रहा है। यह तुलनात्मक दृष्टि स्पष्ट करती है कि जहाँ कुछ पड़ोसी भारत के लिए विकास और संपर्क के अवसर प्रस्तुत करते हैं, वहीं कुछ पड़ोसी रणनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों का कारण बनते हैं।

भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध में चुनौतियां– भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों को चुनौती देने वाली अनेक जटिल परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो विभिन्न स्तरों पर उसकी कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती भूराजनीतिक तनाव और सीमा विवादों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के साथ लंबे समय से आतंकवाद और सीमा संघर्ष के कारण व्यापारिक संबंध लगभग समाप्त हो चुके हैं, जिससे न केवल आर्थिक अवसर सिमटे हैं बल्कि राजनीतिक अविश्वास भी गहराया है। चीन के साथ डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं ने आपसी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 03, March 2025

विश्वास को गहरे स्तर पर क्षति पहुँचाई है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं को सीमित करती हैं। इसी तरह नेपाल के साथ कालापानी और लिपुलेख विवाद के चलते द्विपक्षीय कूटनीति में तनाव बढ़ा, जिससे भारत के "पड़ोसी प्रथम" नीति के प्रभाव पर प्रश्नचिह्न लग गए। आंतरिक अस्थिरता और शासन की सीमाएँ भी पड़ोस में भारत की सक्रियता को धीमा करती हैं। म्यांमार में सैन्य शासन और वहाँ चल रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत की अवसंरचना परियोजनाएँ और संपर्क योजनाएँ बाधित हो रही हैं। वहीं, अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण ने भारत की वर्षों से चली आ रही आर्थिक सहायता और विकास सहयोग की दिशा को झटका दिया है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और रणनीतिक संतुलन प्रभावित हुआ है। व्यापारिक असंतुलन और संरक्षणवाद भी एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आता है। भारत और चीन के बीच विशाल व्यापार घाटा बना हुआ है, जिसमें भारत का निर्यात बेहद सीमित और आयात अत्यधिक बढ़ा हुआ है। यह असंतुलन न केवल आर्थिक दृष्टि से चिंता का विषय है बल्कि रणनीतिक निर्भरता भी बढ़ाता है। इसी प्रकार बांग्लादेश और नेपाल जैसे घनिष्ठ साझेदार देशों के साथ भी कभी—कभी बाजार पहुंच, शुल्कों और गैर—शुल्क अवरोधों की वजह से विवाद खड़े हो जाते हैं, जिससे भारत की "नेबरहुड कनेक्टिविटी" की रणनीति कमजोर होती है।

सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती चीन की "चेकबुक डिप्लोमेसी" और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से आती है। चीन क्षेत्रीय देशों को अवसंरचना निवेश और ऋण देने के जरिये दीर्घकालिक आर्थिक दबाव में फंसा रहा है। पाकिस्तान में सीपेक (CPEC) और श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिनसे भारत की सामरिक उपस्थिति और पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। अंतर—सांस्कृतिक और धार्मिक असहमति, साथ ही डिजिटल सूचना युद्ध, भी भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक और सांप्रदायिक मुद्दे द्विपक्षीय सहयोग को गहराई से प्रभावित करते हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित डिजिटल दुष्प्रचार भारत की विदेश नीति की छवि को कमजोर करने का प्रयास करता है। इस तरह भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक और सामाजिक—सांस्कृतिक स्तर पर उत्पन्न इन चुनौतियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के लिए केवल कूटनीतिक सक्रियता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय साझेदारी की नई परिभाषा गढ़ना अनिवार्य हो गया है।

भारत द्वारा उठाए गए समाधानात्मक कदम तथा भविष्य की रणनीति— भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई समाधानात्मक कदम उठाए हैं। मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई नेबरहुड फर्स्ट नीति इस दिशा में सबसे प्रमुख पहल के रूप में सामने आती है, जिसके अंतर्गत प्राथमिकता दी गई कि सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध समावेशी, व्यावहारिक और आपसी सम्मान पर आधारित हों। यह दृष्टिकोण न केवल पारंपरिक कूटनीतिक मंचों तक सीमित रहा बल्कि क्षेत्रीय सहयोग के अधिक कार्यक्षम और परिणामोन्मुख माध्यमों को महत्व दिया गया। इसके साथ ही भारत ने भौतिक संपर्क और बुनियादी ढांचे में निवेश को विशेष महत्व दिया। कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट, भारत—म्यांमार—थाईलैंड राजमार्ग तथा पाइपलाइन जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थलीय और समुद्री संपर्क को मजबूती प्रदान की गई, जिससे व्यापार और रणनीतिक पहुँच दोनों को व्यापक बढ़ावा मिला। इसी क्रम में अंतर—सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को भी संबंधों का अनिवार्य घटक बनाया गया। नेपाल और

भूटान को विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा वीजा की सुविधा, आपदा प्रबंधन सहयोग तथा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में साझा परियोजनाओं ने भारत के पड़ोसियों के प्रति सहानुभूति और सहभागिता का दृष्टिकोण परिलक्षित किया। रणनीतिक दृष्टि से भी भारत ने पड़ोसी देशों के साथ साझेदारियाँ गहरी की हैं। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त युद्धाभ्यास और हथियार आपूर्ति जैसी गतिविधियों ने रक्षा सहयोग को नई दिशा दी, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा का साझा तंत्र विकसित हुआ। साथ ही भारत ने चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक रणनीतिक विकल्प तैयार किए। चाबहार पोर्ट, अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारे तथा 'एक्ट ईस्ट' जैसे दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत ने नई कनेक्टिविटी की राहें खोलीं और रणनीतिक सहयोग का विस्तार किया।

भविष्य के लिए भारत की रणनीति भी दूरगामी और बहुआयामी है। सबसे पहले, भौगोलिक से आगे भू–सांस्कृतिक कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा, जहां पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, डिजिटल और मानवीय तीनों स्तरों पर संबंध विकसित हों। स्मार्ट आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देते हुए केवल व्यापार नहीं बल्कि निवेश, शिक्षा, स्टार्टअप और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी गहरे सहयोग की संभावना खोजी जा रही है। स्टार्टअप लिंक, ज्ञान–अर्थव्यवस्था और स्किल एक्सचेंज इसके साधन बन सकते हैं। इसके समानांतर, भारत अपने सीमा–वर्ती राज्यों जैसे पूर्वोत्तर, बिहार और बंगाल को सक्रिय भागीदार बनाकर क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित कर सकता है, ताकि पड़ोस के देशों के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध अधिक स्वाभाविक और गहरे स्तर पर विकसित हों। डिजिटल कूटनीति और सूचना–सुरक्षा भी इस भविष्य की रणनीति का अहम आधार होंगी। डिजिटल भुगतान प्रणाली, भारतीय सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और साइबर डिफेंस सहयोग के माध्यम से पड़ोसियों को भारत–केंद्रित डिजिटल नेटवर्क से जोड़े रखना आवश्यक होगा। अंततः, दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ जुड़ाव और पड़ोसी देशों को प्राथमिक भागीदार बनाना भारत की समग्र विदेश नीति को संतुलित व सक्षम दिशा देगा। इस प्रकार भारत की सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संतुलित पड़ोसी नीति न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देगी बल्कि भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य दोनों में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगी।

निष्कर्ष: - भारत ने इक्कीसवीं सदी में विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित आर्थिक दर्शन के अनुरूप अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक कूटनीति को रणनीतिक रूप से परिपक्व किया है। जहां नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के साथ समावेशी विकास की साझेदारी सुदृढ़ हुई है, वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे जटिल पड़ोसियों के साथ आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाई गई है।

अंततोगत्वा भारत की पड़ोसी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह क्षेत्रीय स्थिरता और साझेदारी के माध्यम से दक्षिण एशिया में न्याय और समृद्धि की स्थापना कर सकती है, जैसा कि अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था, "हमारी सफलता को केवल एक ही पैमाने से मापा जाना चाहिए क्या हम मानव जाति – प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए के लिए न्याय और समृद्धि हासिल कर सके।

संदर्भ सूची–

1. **WITS (World Bank).** (2022). *India Product Exports and Imports to Bangladesh.* Retrieved from: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IND/Year/2022/TradeFlow/EXPIMP/Partner/BGD/Product/All-Groups
2. **IBEF.** (2023). *Exploring India–Bangladesh Trade & Economic Relations.* Retrieved from: https://www.ibef.org/indian-exports/india-bangladesh-trade
3. **DGFT, Ministry of Commerce, Government of India.** (2023). *Monthly Bulletin on Foreign Trade Statistics (2022–23).* Retrieved from: https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/1aee3044-9582-4c17-b7c3-c791d9563b8f/Monthly%20Bulletin%20on%20Foreign%20Trade%20Statistics%20April%202022-23.pdf
4. **WTO.** (2023). *Nepal Imports by Partner.* Retrieved from: https://ttd.wto.org/en/profiles/nepal
5. **TrendEconomy.** (2022). *Nepal Imports from India.* Retrieved from: https://trendeconomy.com/data/h2/Nepal/TOTAL
6. **OEC.** (2023). *Nepal Exports, Imports & Trade Partners.* Retrieved from: https://oec.world/en/profile/country/npl
7. **Government of Bhutan.** (2022). *Economic and Hydropower Reports.* Thimphu: Ministry of Economic Affairs.
8. **DGFT, Ministry of Commerce, Government of India.** (2022). *India's Trade with Myanmar.*
9. **DGFT, Ministry of Commerce, Government of India.** (2022–23). *India–China Bilateral Trade Statistics.*
10. **DGFT, Ministry of Commerce, Government of India.** (2022). *India–Pakistan Trade Data.*
11. **Ministry of External Affairs, Government of India.** (2022). *India's Development Cooperation in Afghanistan.*